भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1290

(11 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत लाभार्थियों की प्रतीक्षा सूची

1290. श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा 14 अगस्त, 2024 के पत्र के संदर्भ में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के दिशानिर्देशों के अंतर्गत दाहोद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्थायी प्रतीक्षा सूची में उक्त योजना के अंतर्गत लगभग 11,000 लाभार्थियों द्वारा अब इसका लाभ नहीं उठा पाना दर्शाते हुए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या गांव के 11,000 लोगों के लिए मार्च, 2025 तक मकान स्वीकृत होने की संभावना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी)

(क) से (ख): ग्रामीण विकास मंत्रालय पात्र ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान करके बुनियादी सुविधायुक्त पक्के आवासों के निर्माण के लक्ष्य के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिनांक 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) कार्यान्वित कर रहा है। पीएमएवाई-जी के तहत, प्रारंभिक लक्ष्य वित्त वर्ष 2016-17 से 2023-24 के दौरान 2.95 करोड़ आवासों का निर्माण करना था और इन सभी आवासों को मंजूरी दे दी गई है और दिनांक 06.02.2025 तक इस लक्ष्य की तुलना में 2.69 करोड़ आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। भारत सरकार ने आवास+ (2018) सूची (अपडेशन के बाद) के लाभार्थियों को पूर्णतः लाभ प्रदान करने और एसईसीसी 2011 पीडब्ल्यूएल के अनुसार शेष पात्र परिवारों को 2 करोड़ पक्के आवासों की समग्र सीमा के भीतर सहायता प्रदान करने हेतु वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान 5 और वर्षों

के लिए योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। भारत सरकार ने संशोधित बहिष्करण मानदंडों का उपयोग करके पात्र ग्रामीण परिवारों की पहचान करने के लिए आवास + सूची को अद्यतन करने के कार्य को भी मंजूरी दी है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दिनांक 14 अगस्त, 2024 के पत्राचार (दिनांक 17.08.2024 को ई-हस्ताक्षरित) के माध्यम से केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा यथा अनुमोदित पीएमएवाई-जी के अगले चरण (2024-25 से 2028-29) के कार्यान्वयन के लिए योजना में संशोधनों की जानकारी दी थी।

तदनुसार, पीएमएवाई-जी के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 84,37,139 आवासों का लक्ष्य आवंटित किया गया है जिसमें मौजूदा एसईसीसी 2011 आधारित पीडब्ल्यूएल और आवास+ 2018 डेटाबेस से गुजरात को आवंटित 2,99,011 आवासों का लक्ष्य शामिल है। इसके अलावा, मंत्रालय राज्यों को लक्ष्य आवंटित करता है और उसके बाद जिलों/ब्लॉकों/ग्राम पंचायतों को लक्ष्यों का आवंटन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। पात्र लाभार्थियों को आवासों की मंजूरी भी राज्य द्वारा दी जाती है।

योजना के अंतर्गत संशोधित बहिष्करण मानदंडों का उपयोग करते हुए अतिरिक्त पात्र ग्रामीण परिवारों की पहचान के लिए आवास+ सूची को अद्यतन करने के लिए राज्य द्वारा आवास+ सर्वेक्षण किया जा रहा है।

*****